

पहले मुख्य समाचार।

- उत्तर प्रदेश सहित छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर किए हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा- जल संसाधनों के समुचित उपयोग और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा यह कदम।
- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 23 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। मंत्रिपरिषद ने पीआरडी जवानों और उनके परिवार वालों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का लिया फैसला।
- लोगों के बीच यूपीआई से लेन-देन पर नहीं लगेगा कोई शुल्क। वित्त मंत्रालय ने कहा- छोटे व्यापारियों के लिए भी दो हजार रुपये तक का लेन-देन रहेगा निःशुल्क।
- प्रदेश में शिक्षकों के पंद्रह हजार बारह पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू।

उत्तर प्रदेश सहित देश के छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कल यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पानी से जुड़ा यह दसवां विवाद है, जो अब सुलझने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने किशाऊ परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है।

इस परियोजना का लगभग 90 प्रतिशत वित्तीय भार भारत सरकार वहन करेगी और शेष 10 प्रतिशत राशि 1994 के समझौते के अनुसार भागीदार राज्यों द्वारा वहन की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस समझौते को जल संसाधनों के समुचित उपयोग और भावी पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि परियोजना के साकार होने से उत्तर प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से अन्नदाताओं को संबल, पेयजल की उपलब्धता को मजबूती और यमुना की अविरलता को नई शक्ति मिलेगी। इस परियोजना के तहत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बहने वाली टोंस नदी पर कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनेगा, जहाँ एक हजार 562 मिलियन क्यूबिक मीटर जल संग्रहण होगा। इससे 97 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और एक हजार 476 मिलियन यूनिट स्वच्छ जल विद्युत भी प्राप्त होगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में तेइस अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने मथुरा के छाता में एथेनॉल प्लांट को मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि दो सौ करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस प्लांट में साल के ग्यारह महीने इथेनॉल बनाने का काम होगा।

19 वर्ष पहले शुगर फैक्ट्री बंद होती है। वहां माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में जो प्रस्ताव पास हुआ है, इथेनॉल प्लांट जो गन्ने से, मक्का और धान गन्ना समाप्त होने के बाद मक्का और धान से एथेनॉल बनाया जाएगा। यह प्लांट साल में 11 महीने चलेगा। जो भी इथेनॉल की मात्रा 3 करोड़ 96 लाख लीटर एक साल में इथेनॉल बनेगा।

मंत्रिपरिषद ने अलीगढ़ में नई यूनिवर्सिटी को भी मंजूरी दे दी। मंत्रिपरिषद ने इसके लिये लैटर ऑफ इंटेन्ट जारी किया है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत प्रदेश के पीआरडी जवानों और उनके परिवार वालों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा दिये जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। मंत्रिपरिषद ने अयोध्या में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड-एनएसजी का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय-एमएचए को निःशुल्क भूमि हस्तांतरित करने को भी मंजूरी दे दी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वह करीब तीन करोड़ की लागत से बने कल्याण मंडपम का लोकार्पण करेंगे। हमारे गोरखपुर प्रतिनिधि ने बताया कि जंगल नकहा नंबर दो में तीन सौ लोगों की क्षमता वाला यह कल्याण मंडपम दो तल में बनाया गया है। मुख्यमंत्री आज ही आईएमए के चैरिटेबल ब्लड सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कल से सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत होगी। इसे लेकर प्रदेश भर में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में अभियान के संबंध में समीक्षा बैठक कर इसे सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे हैं। इसी क्रम में हापुड़ जिले के प्रभारी मंत्री के.पी. मलिक ने कल अधिकारियों के साथ बैठक कर एक माह तक चलने वाले इस अभियान की कार्य योजना के बारे में चर्चा की।

शाहजहांपुर के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अधिकारियों को सेवा संकल्प अभियान के सभी कार्यक्रम प्रभावी ढंग से कराने और अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने बताया कि सत्रह सितंबर से सत्रह अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पच्चीस वर्षों के सेवाकाल की जनकल्याणकारी उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाना और नागरिकों को विकसित भारत-2047 के संकल्प से जोड़ना है।

सेवा संकल्प के अभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासन प्रशासन और संगठन के समन्वय के साथ कार्य योजना तैयार की है। 17 सितंबर को शाहजहांपुर जनपद में रक्तदान का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद 17 तारीख से लगातार 17 अक्टूबर तक बहुत सारे अभियानों के माध्यम से जन कल्याण की योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को देने का काम भी पूर्ण होगा।

वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई से कितनी भी राशि के लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए दो हजार रुपये तक का लेन-देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग छानवे प्रतिशत लेन-देन अप्रभावित रहेगा।

दो हजार रुपये से ज्यादा के व्यक्ति से व्यवसायी लेनदेन पर शून्य दशमलव चार प्रतिशत का मामूली एमडीआर लगेगा, जबकि पचहत्तर हजार रुपये और उससे अधिक के हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए, एमडीआर की सीमा तीन सौ रुपये प्रति लेनदेन होगी। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यवसायी या कारोबारी का यह शुल्क यूपीआई से भुगतान करने वाले ग्राहकों पर न लगाएं।

अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब अंतिम भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि भविष्य में निर्माण की गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए निर्माण कंपनियों से बैंक गारंटी ली जा रही है। साथ ही निर्माण के अंतिम भुगतान का ऑडिट भी थर्ड पार्टी से कराने का फैसला लिया गया है। श्री मिश्र ने बताया कि वहां अब राम कथा संग्रहालय का काम शुरू होगा।

संग्रहालय का जो सबसे बड़ा कार्य अब शुरुआत होगी आने वाले 10 अक्टूबर तक टेंडर जारी की जो टेक्नोलॉजी होगी उसका हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा वह बनाना है और उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। अनुमान है कि टेंडर फाइनलाइज जो कि अक्टूबर के अंत तक कदाचित हो जाएगा। उसके बाद लगभग 6 महीने लगेगे गैलरी को कंप्लीट करने में।

प्रदेश में शिक्षकों के पंद्रह हजार बारह पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गयी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ प्रशांत कुमार ने बताया कि आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत सहायक अध्यापक सम्बद्ध प्राइमरी के आठ सौ सनतानवे रिक्त पदों और बेसिक शिक्षा विभाग के तहत सहायक अध्यापक शहरी के ग्यारह हजार पांच सौ आठ रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। इनके लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। आयोग ने प्रवक्ता संवर्ग के दो हजार छह सौ सात पदों के लिए भी विज्ञापन जारी कर दिए हैं। इनके लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन की प्रक्रिया अठारह सितम्बर से शुरू होगी।

अंतरिक्ष यात्री और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने लखनऊ में चल रहे गोमती पुस्तक महोत्सव में कल अपनी किताब द सेकेंड ऑर्बिट का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों और युवाओं के साथ संवाद किया और अपनी अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव भी साझा किए।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण-सीसीपीए ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि यह जुर्माना गलत ट्रेड प्रैक्टिस, गलत अनुबंध और डार्क पैटर्न के लिए लगाया गया है। इसमें राइड कन्फर्म होने से पहले राइडर्स से ज्यादा पैसे देने के लिए कहा जाता था।

यह कार्रवाई भारत में चल रहे कैब और बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म की सेक्टर-वाइड जांच के बाद की गई है। जांच के दौरान सीसीपीए ने पाया कि रैपिडो का एल्गोरिदम कन्फर्म शेमिंग जैसा था, जो डार्क पैटर्न की रोकथाम और रेगुलेशन के लिए दो हजार तेइस के दिशानिर्देशों के तहत पहचाना गया डार्क पैटर्न है। इसमें उपभोक्ता को ज्यादा पैसे देने के लिए सहमत नहीं होने पर राइड खोने का डर पैदा करता है।
